साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 31 जुलाई-06 अगस्त 2023 वर्ष-9, अंक-16

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

प्रधानमंत्री बोले-किसानों के दर्द और जरूरतों को समझती है केंद्र सरकार

समारोह में मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली हुए शामिल

मप्र के 76 लाख किसानों को मिली 1680 करोड़ रु. की सम्मान निधि

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही (पीएम-किसान) की 14वीं किस्त के रूप में 17 हजार करोड़ किसानों के बैंक खातों में जमा किए। राजस्थान के सीकर से मोदी ने 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए और सल्फर कोटेड यूरिया लांच की। साथ ही, ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स पर 1600 से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों के ऑनबार्डिंग का शुभारंभ किया। वहीं मध्य प्रदेश के 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में एक हजार 680 करोड़ रुपये अंतिरत हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए। गौरतलब है कि मप्र के 76 लाख से अधिक किसान आते हैं। इन सभी को शिवराज सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के माध्यम से चार हजार रुपए अपनी ओर से दे रही है। इस राशि को अब बढ़ाकर छह हजार किया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्रयासों पर कहा कि किसानों के सशक्तीकरण के लिए कई पहल की गई हैं।

किसानों को सीधा लाभ मिलेगा- प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू किए 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्हें किसानों की जरूरतों के लिए वन-स्टॉप शॉप में विकसित किया जा रहा है। गांव व ब्लॉक लेवल पर इन केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यहां किसानों को बीज, खाद, खेती के औजार व अन्य मशीनें भी मिलेंगी। ये केंद्र खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। वर्षात से पहले ऐसे और 1.75 लाख केंद्र खोले जाएंगे।

पीएम ने दिया किसानों को सुरक्षा कवचः तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जबसे पीएम ने कार्यभार संभाला, उनकी प्राथमिकता रही है कि गांव-गरीब-किसानों की प्रगति हो।कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े, नवाचार बढ़े, तकनीक का समर्थन हो, छोटे किसानों की आय बढ़े, कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश में योगदान दे सकें। 2014-15 में कृषि मंत्रालय का बजट 23 हजार करोड़ होता था जो अब पांच गुना अधिक 1.25 लाख करोड़ हो गया है। किसान कितना भी परिश्रम कर लें, सरकार की नीतियां अनुकूल हों, फिर भी उन्हें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। जब प्रकृति का प्रकोप आता है तो फसलों को नुकसान होता ही है। इसके लिए मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बड़ा सुरक्षा कवच किसानों को दिया है।

नई व्यवस्था का निर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे किसानों के लिए देश के किसी भी हिस्से से उपज को बाजार तक ले जाना आसान हो जाएगा।केंद्र की मौजूदा सरकार किसानों के दर्द और जरूरतों को समझती है व किसानों के खर्चे कम करने और जरूरत के समय उनका समर्थन करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 9 वर्षों में बीज से बाजार तक नई व्यवस्था का निर्माण किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से करोड़ों किसान मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान के आधार पर इष्टतम निर्णय ले रहे हैं।

किसानों के साथ

पीएम ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें सीधे किसानों के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर की जाती है। आज की 14वीं किस्त को मिला लें तो अब तक 2.60 लाख करोड़ से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं जिससे किसानों को विभिन्न खर्चों को कवर करने में फायदा हुआ है। किसानों का सामर्थ्य, किसानों का परिश्रम, मिट्टी से भी सोना निकाल देता है इसलिए सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

गांवों में सारी सुविधाएं होंगी | प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास तभी संभव है, जब गांवों का विकास होगा इसीलिए सरकार गांवों में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है जो सिर्फ शहरों में ही मिलती थी। दशकों तक गांवों में अच्छे स्कूलों, शिक्षा की कमी के कारण गांव-गरीब पीछे रह गए, अफसोसजनक रहा कि पिछड़े-आदिवासी समाज के बच्चों के पास सपनों को पूरा करने का कोई साधन नहीं था। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के लिए बजट और संसाधन बढ़ाए।

प्रदेश में सोयाबीन धान-मक्का की बोवनी लक्ष्य से दूर

» मप्र के आठ जिलों में कम वर्षा का दिखने लगा असर

» अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली में सूखे जैसे हालात

भोपाल। प्रदेश में खरीफ फसलों की बोवनी चल रही है। अभी तक 124 लाख हेक्टेयर में बोवनी हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में तो अधिक है, पर इस वर्ष के लक्ष्य से 24 लाख हेक्टेयर कम है। इस बार 148 लाख हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के आठ जिलों में अब तक हुई कम वर्षा का यह असर है। अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली में यदि इस माह वर्षा नहीं होती है तो सूखे जैसे हालात हो जाएंगे। यदि वर्षा हो गई तो फसलों की बोवनी बढ़ने से लक्ष्य हासिल हो जाएगा। प्रदेश में पिछले साल 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोवनी हुई थी। वर्ष 2023 में 148.76 लाख हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। सोयाबीन की बोवनी का लक्ष्य इस बार साढ़े 52 लाख हेक्टेयर रखा गया है।

ज्वार-बाजरा की बोवनी अधिक

धान के लिए लक्ष्य साढ़े 34 लाख हेक्टेयर रखा गया है। अभी 20.84 लाख हेक्टेयर में बोवनी हो चुकी है, जो पिछले वर्ष इस अवधि में हुई बोवनी की तुलना में छह लाख हेक्टेयर अधिक है। तुअर की बोवनी तीन लाख 60 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि, चार लाख 66 हेक्टेयर में फसल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ज्वार और बाजरा की बोवनी पिछले साल की तुलना में अधिक हुई है लेकिन लक्ष्य से अभी दूर है। कपास की बोवनी भी लक्ष्य के अनुरूप हो चुकी है।

बाघ गणना के राज्यवार आंकड़े जारीः कर्नाटक दूसरे, उत्तराखंड तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और तमिलनाडु 5वें नंबर पर

एक बार फिर मध्यप्रदेश के माथे पर सजा टाइगर स्टेट का ताज

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने बाघ गणना के राज्यवार आंकड़े जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ अव्वल रहा है। मध्य प्रदेश ने लगातार दूसरी बार कुल तीन बार अपना टाइगर स्टेट का दर्जा कायम रखा है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहां 563 बाघ हैं। उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ मिले हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वैश्विक बाघ दिवस का आयोजन किया गया।

इस दौरान केंद्रीय वन राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विस्तृत रिपोर्ट जारी की। 2006 में बाघ संरक्षण प्रयासों को गति दी गई थी। इसके बाद से लगातार बाघों की संख्या बढ़ ही रही है। 2006 में 300 बाघों के साथ मध्य प्रदेश सबसे अधिक बाघों वाला राज्य था। इसके बाद 2010 में यह घटकर 257 हो गए और तब मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा कर्नाटक ने छीन लिया था। 2014 में मप्र में 308 बाघ थे और 2018 में 526 बाघ। 2018 में मध्य प्रदेश ने सिर्फ दो बाघ अधिक होने की वजह से कर्नाटक से एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया था। इसके बाद मप्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चार साल में प्रदेश में 259 बाघ बढ़े, जबकि कर्नाटक में सिर्फ 39 बाघ। अब मध्य प्रदेश और कर्नाटक का अंतर 2018 के दो बाघ से बढ़कर 2022 में 222 का हो गया है।

देश में बढ़ता गया बाघों का कुनबा

2006 में देश में 1411 बाघ थे, जो एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहा था। 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3682 बाघ हो गए हैं। हर राज्य में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत की दुनियाभर के बाघों में हिस्सेदारी 75 फीसदी हो गई है। 2018 में 2461 बाघ थे, जबकि यह 2022 में बढ़कर 3080 हो गए हैं। तीन-चौथाई बाघ देश में हैं। देश में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो 75796 वर्ग किमी में फैले हैं।

पीएम ने की थी यह घोषणा | 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम 3167 बाघ होने की घोषणा की थी। उस समय के आंकड़े सिर्फ कैमरा-ट्रैप इलाकों से आए थे। वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने कैमरा-ट्रैप के साथ-साथ नॉन-कैमरा-ट्रैप इलाकों से भी आए आंकड़ों का विश्लेषण किया।

मध्य प्रदेश को बधाई। नई बाघ गणना के आंकड़ों में 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश देश का सबसे अधिक बाघ वाला राज्य बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश की बाघों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ गहन संरक्षण और निगरानी से ही यह संभव हो सका है।

भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन मंत्री

अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेशवासियों के सहयोग और वन विभाग के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, चार वर्षों में हमारे प्रदेश में जंगल के राजा बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। मैं पूरे प्रदेश की जनता को, वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण में उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं। आइये हम सब मिलकर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण का पुनः संकल्प लें।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

रीवा के किसान ने छह एकड़ में की खेती, साल में तीन बार फसल

लौकी-भंटे की खेती से किसान बन रहे लखपति

» किसान करें लौकी की खेती, होगी दोगुनी कमाई

» किसान ने ट्रेडिशनल छोड़ खेती का वैज्ञानिक तरीका अपनाया

» मजदूरी महंगी होने से विनोद मशीन की सहायता से खेती कर रहे

रीवा। जागत गांव हमार

आमतौर पर लौकी की खेती कई किसान करते हैं, लेकिन रीवा के एक किसान की चर्चा हो रही है। वह लौकी की खेती कर दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले दो साल से वह मचान पद्धति से 6 एकड़ में सब्जी उगा रहे हैं। इस पद्धति की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें नुकसान कम होता है, जिससे पैदावार बढ़ जाती है। साल में तीन बार फसल लेते हैं। रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान का बरेही गांव के रहने वाले किसान विनोद गौतम लॉकडाउन से पहले तक विनोद गेहूं, चना, सरसों, धान और सोयाबीन की खेती करते थे। इसमें लागत बढ़ती जा रही थी। मुनाफा लगातार कम हो रहा था। यूट्यूब पर वीडियो देख उन्हें आइडिया आया। इसके बाद महाराष्ट्र के किसान के फैमिली से ट्रेडिशनल छोड़ खेती का वैज्ञानिक तरीका अपनाया। साल 2020-21 से बागवानी में हाथ आजमाया। सब्जियों की खेती के लिए इनके पास 30 एकड़ का रकबा है। इसमें 6 एकड़ में लौकी और बाकी में टमाटर, बैंगन, खीरा, करेला, कोहड़ा (कद्दू), मिर्च, आलू, प्याज की बोवनी की है। मजदूरी महंगी होने से विनोद मशीन की सहायता से खेती कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मजदूरी देने से लागत बढ़ जाती है, इसलिए लागत कम करने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं।

मचान पद्धति मचान विधि फसलों को तैयार करने की उत्तम विधि है। इसमें फसल जमीन की सतह पर ना फैलकर तार और रस्सियों के सहारे खुले वातावरण में फैलाकर विकास करते हैं, जिससे फसलों में रोग नहीं लगते। मचान में लौकी, खीरा, करेला जैसी बेल वाली फसलों की खेती की जा सकती है। इसमें खेत में बांस या तार का जाल बनाकर सब्जियों की बेल को जमीन से ऊपर पहुंचाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि किसान अपनी फसल 90-95 प्रतिशत तक बचा सकते हैं। इससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है।

मचान वाली खेती

मचान विधि से खेती वर्तमान समय की जरूरत है। हम बांस व लोहे के डंडे को खेत में गड्ढा बनाकर गाड़ देते हैं। फिर पतले तार या रस्सी के सहारे लौकी के पौधे को बांध देते हैं। ऐसे में पेड़ की डाल ऊपरी सतह पर आ जाती है। इस विधि से खेती में धान और गेहूं की अपेक्षा खर्च जरूर बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न अच्छा मिल जाता है। मचान पद्धति में सब्जियों की पैदावार अच्छी इसलिए होती है, क्योंकि जमीन के पौधों का संपर्क नहीं रहता है। यह व्यवस्था पौधों को सड़ने से बचाती है। लौकी की गुणवत्ता जमीन के संपर्क में रहने वाली लौकी की अपेक्षा बेहतर है।

तैयार करें लौकी उगाने के लिए खेत

खेत में दिन रात बागवानी करने वाले दीपक तिवारी ने बताया कि पहले खेत का चयन करें। फिर गर्मी के मौसम में अच्छी से जुताई करें। हो सके तो एक दो बार प्लाऊ जरूर चलाएं। इससे नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाए। इसके बाद हैरो से मिट्टी को महीन बना दे। मशीन से खेतों की बेड तैयार करें। खेत तैयार होने के बाद हरी खाद, गोबर की खाद, थोड़ा सा डीएपी का डोज तैयार कर खेत में डाल दें। फिर अच्छी से अच्छी बेड बनाएं। मजदूरों की मदद से प्लास्टिक मल्चिंग तैयार करें।

नर्सरी के पौधे देते हैं उपज

किसान विनोद गौतम ने बताया कि नर्सरी के पौधे आम पौधों से ज्यादा उपज देते हैं। नर्सरी के लिए सीजन के अनुसार बीज का चयन करें। हो सके तो कृषि वैज्ञानिकों की समय समय पर सलाह लें। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में नमी की कमी न होने दें। गर्मी के दिन में जब तक बीज अंकुरित न हो जाए, तब तक प्रतिदिन फव्वारे से सिंचाई करें। पहले एक जगह नर्सरी तैयार कर लें, फिर दूरी के हिसाब से नर्सरी लगाएं। लौकी को डेढ़ से दो फीट की दूरी पर लगाएं। नर्सरी से अगल और बगल वाली क्यारी की दूरी करीब दो से ढाई फीट रखें।

लागत तो ज्यादा कमाई

किसान का कहना है कि लौकी की खेती में लागत तो जरूर ज्यादा है, लेकिन आमदनी भी अच्छी है। औसतन एक एकड़ में तैयार लौकी की खेती में 30 से 40 हजार की लागत आती है। वहीं कमाई 70 से 80 हजार तक होती है। कुल मिलाकर दोगुना मुनाफा है। हम धान और गेहूं के खेत से महज 10 से 15 हजार सालाना कमाते हैं। नए-नए आइडिया से हम खर्च घटा सकते हैं। इससे कमाई ज्यादा से ज्यादा हो। मशीन और नई विधियों का इस्तेमाल किया जाता है।

विनोद की जुबानी, उनकी सफलता की कहानी

एमकॉम पास करने के बाद से मैं बरेही गांव में धान और गेहूं की खेती करता रहा हूं। 58 साल की उम्र तक ट्रेडिशनल खेती की, लेकिन इसमें लागत और मुनाफा का अंतर पहले के मुकाबले कम होता गया। लॉकडाउन के दौरान घर में रहना मेरे लिए उपयोगी साबित हुआ। इस दौरान यूट्यूब पर महाराष्ट्र के कई किसानों से जुड़ा। उनसे नियमित रूप से नए तरीके से खेती करने के टिप्स लेता।

दरअसल, महाराष्ट्र के कई किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। उनका झुकाव परंपरागत खेती से हटकर स्मार्ट खेती की ओर अधिक है। मैंने महाराष्ट्र के किसानों के नए प्रयोग के बारे में सुन रखा था। इसी वजह से उनकी खेती करने के तरीकों को लेकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपर्क में आया। यहीं से मेरा रुझान सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ गया।

यूट्यूब से ही महाराष्ट्र के किसानों के नए-नए आइडिया से खेती के वीडियो देखा। बड़े बेटे गौरव गौतम ने मेरी सोच का समर्थन किया। फिर एक बागवान फैमिली की मदद लेकर सब्जी की खेती शुरू कर दी। हम यहां के बागवानों से उलट हर मौसम में सब्जी की पैदावार ले रहे हैं। मजदूरों का उपयोग सिर्फ सब्जियों की तुड़ाई के काम में करते हैं। बाकी काम मशीन से किया जा रहा है।

जरूरत के लिए धान-गेहूं खरीद रहे

दो साल बागवानी कर नया तजुर्बा आया है। ऐसे में इस वर्ष 30 एकड़ में सब्जी लगाने का निर्णय लिया। 6 एकड़ में लौकी, एक एकड़ में बैंगन, दो एकड़ में खीरा, दो एकड़ में टमाटर लगाया है। अभी लौकी, धनिया, मिर्च, गोभी आदि लगाने की तैयारी चल रही है। अब कुल मिलाकर हम घर में भी खाने के लिए भी धान और गेहूं नहीं उगाते। जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं।

लौकी की खेती की लागत

तीन हजार में प्लाऊ, दो हजार रुपए जुताई के लिए, दो हजार में हैरो, एक हजार में बेड की तैयारी, दो हजार में हरी खाद, गोबर की खाद, थोड़ा सी डीएपी। तीन हजार में प्लास्टिक मल्चिंग के लिए, दो हजार ड्रिप इरिगेशन पर खर्च होता है। वहीं, तीन हजार रुपए का बीज, दो हजार लेबर से नर्सरी तैयार करवाने में, दो हजार रुपए नर्सरी तैयार करने में। मचान के लिए पांच हजार रुपए का बांस, दो हजार रुपए की रस्सी। पांच हजार में तार-बाड़ी और पांच हजार रुपए फसल तोड़ने के लिए मजदूरी पर खर्च आता है।

पौधों में लगने वाले रोग

सफेद मक्खी: ये छोटा सफेद कीट है, जो फसलों की कोमल पत्तियों के रस को चूसकर कमजोर बना देता है। यह मक्खी विषाणु भी फैलाती है। सफेद मक्खी से फसल बचाने के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिली. प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करते हैं।

पत्ती खाने वाले कीड़े: लौकी में फूल आने के समय हरे रंग के पत्ती खाने वाले कीड़े का प्रकोप देखने को मिलता है। ये कीड़े दिन में पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं और रात के अंधेरा होने के बाद पत्तियों से बाहर निकलकर पत्तियों को खाते हैं। इन कीड़ों से लौकी को बचाने के लिए प्रोफेक्स सुपर 1.5 मिली. प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना पड़ता है।

फल सड़न रोग: इस बीमारी में लौकी के छोटे फल सड़ने लगते हैं। साथ ही, बड़े होने पर काले रंग के दाग बन जाते हैं। इससे पैदावार में काफी कमी हो जाती है। लौकी को सड़ने व दाग से बचाने के लिए मिराडोर 15 मिली. प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 12 दिनों के अंतर पर स्प्रे करना पड़ता है।

बड़वानी जिले के किसान ने डेढ़ बीघा में की खेती, एक पौधे पर खर्च 2 रुपए, बैंगन निकले 6 किलो

बैंगन की खेती में लागत 22 हजार, कमाई दो लाख

बड़वानी। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय से महज तीन किलोमीटर कुक्षी बायपास के पास रहने वाले किसान संतोष काग पिछले साल तक परंपरागत खेती किया करते थे, लेकिन लागत और मुनाफे का अंतर बढ़ने से हर साल घाटा होता था।

मेहनत और लागत के मुकाबले मुनाफे का अंतर लगातार कम होता जा रहा था। ऐसे में वो चाहते थे कि कोई ऐसी फसल लगाएं, ताकि परंपरागत खेती पर निर्भरता कम की जा सके। इसी दौरान उनके कुछ दोस्तों ने बताया कि बैंगन की खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही, दोस्तों ने बैंगन की खेती करने के तरीके भी बताए। दोस्तों की बात से प्रभावित होकर संतोष काग ने बैंगन की खेती शुरू की। इस साल इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है। बड़े स्तर पर बैंगन की खेती का यह उनका पहला सीजन है। अभी तक दो लाख की कमाई हो चुकी है। आने वाले दो महीनों में दो लाख रुपए की कमाई और होने की उम्मीद है, जबकि बैंगन की खेती पर महज 20 से 22 हजार का खर्च आया है। पहली बार मैंने 2022 में प्रायोगिक तौर पर बैंगन के 50 से 60 पौधे लगाए। फीडबैक अच्छा मिलने पर इस साल बड़े स्तर पर बैंगन की खेती की है। सब्जियों के भाव दिनो दिन बढ़ने से किसानों को मोटा मुनाफा कमाते देखा, तो मैंने भी खेती शुरू कर दी। हमारे गांव के अलावा जिले के कई गांवों के परंपरागत खेती करने वाले किसानों का रुझान भी सब्जी की खेती की ओर बढ़ा है। सब्जी की खेती के भंडारण की व्यवस्था हो, तो ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। मेरे पास पांच एकड़ खेत है। पहले मैं खेत में पारंपरिक फसलें उगाता था, लेकिन उतनी आमदनी नहीं मिल पाती थी। इसके बाद डेढ़ बीघा खेत में बैंगन लगाया। पारंपरिक खेती के साथ-साथ सब्जियों की खेती भी शुरू की। यह देखकर कि कुछ पड़ोसी भी सब्जी की खेती करने लगे हैं। क्योंकि सब्जियों से आमदनी खूब हो रही है। मैंने कुल 5 एकड़ खेत में से डेढ़ बीघा में करीब 6 हजार पौधे लगाए हैं।

लोकल बाजार में बढ़ रही डिमांड

छोटी जोत के किसान संतोष का कहना है कि बैंगन की लोकल मार्केट में अच्छी डिमांड है। वे पहले सब्जियों को अन्य स्थानों पर भेजने के बजाय लोकल मार्केट में बेचते थे। अब लोकल मार्केट की मंडी छोटी होने की वजह से बैंगन की खेप बाहर भेजनी पड़ती है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ ही इंदौर और भोपाल के आसपास के बाजारों में संतोष के खेत से बैंगन की खेप पहुंच रही है।

अब टमाटर की तरफ बढ़ा रहे अपना रुझान

संतोष काग कहते हैं कि टमाटर की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। बाजार में टमाटर 150 से 180 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है, इसलिए टमाटर की खेती की करने की योजना बनाई है। खरीफ की बोवनी के अलावा सब्जी की खेती शुरू कर दी है। टमाटर के दाम बढ़ने से अब किसानों को उम्मीद है कि टमाटर के उत्पादन से उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगाद्य यही वजह है कि संतोष भी अपने खेत में टमाटर की खेती कर रहे हैं।

चुनौती से निपटने की करें तैयारी

बैंगन की खेती में सबसे बड़ी चुनौती मौसम की रहती है। बैंगन का पौधा गर्म जलवायु से आता है। यह कम तापमान और सर्दी के प्रति बेहद संवेदनशील पौधा है। इसके लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की जरूरत होती है, जबकि मिट्टी का तापमान 20 एष्ट (68 एख) से कम नहीं होना चाहिए। बैंगन की रोपाई के दौरान अधिक ठंड मौसम पौधे के विकास को रोक देता है, इसलिए अगर आप बैंगन की खेती कर रहे हैं, तो मौसम की चुनौती से निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए पौधों को ढंक कर रखना पड़ेगा।

एक पौधे पर डेढ़ से दो रुपए का खर्च

एक पौधे पर करीब डेढ़ से दो रुपए का खर्च आया है। हाल में इन पौधों से बैंगन की तुड़ाई कराई थी। हर पौधे से 5 से 6 किलो बैंगन निकला था। पहली बार में करीब 25 क्विंटल से ज्यादा बैंगन की पैदावार मिली है। जिसे मैंने इंदौर और भोपाल के व्यापारियों को बेचा था। अभी तक करीब दो लाख रुपए के बैंगन बेच चुका हूं द्य अब पौधे बड़े हो गए हैं। बैंगन सभी पौधों में फिर से लगने लगा है। अभी एक बार और तुड़ाई होगी द्य इस बार भी दो लाख रुपए तक की आमदनी होने की उम्मीद है। बैंगन की खेती क्यारियों में की गई है, क्योंकि पानी की कमी है। पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं।

25 दिन बाद पौधे तैयार बोवनी के 21 से 25 दिन पश्चात पौधे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैगन के पौधों की रोपाई शाम के समय की जानी चाहिए। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इस क्रिया से पौधों की जड़ों का मिट्टी के साथ संपर्क होता है। मौसम के अनुसार 3 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई की जा सकती है। फसल की समय-समय पर निकाई व गुड़ाई करनी पड़ती है। पहली निकाई-गुड़ाई रोपाई के 20-24 दिन बाद और दूसरी 40 से 50 दिन के बाद करें।

पौधों में लगने वाले कीट

तना व फल भेदक: यह कीट पत्तों के साथ-साथ बैंगन को अंदर से भी खा जाते हैं। इसके कारण फसल की उपज को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए कीट पर प्रकोप होने पर नीम के बीज का रस मिलाकर घोल बनाएं। 15 दिन के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी प्रकोप कम न हो तो कीटनाशक दवा जैसे-इंडोसल्फान 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर या साइपरमेथ्रिन 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नीम के बीज के घोल में मिलाकर छिड़काव करें।

जैसिड: इस प्रकार के कीड़े पत्तों के नीचे चिपक कर रस चूसते हैं। इसकी वजह से पत्तियों का रंग पीला और पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसके लिए रोपाई से से पहले पौधों की जड़ों को कानफीडर दवा के 1.25 मिली प्रति लीटर की दर से बने घोल में 2 घंटे तक डूबाना चाहिए।

एपीलैक्ना बीटल: एपीलैक्ना बीटल पत्तों को खाने वाला लाल रंग का छोटा कीड़ा होता है द्य यह कीट पौधों को शुरुआती दौर में नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियों को छलनी जैसा बना देता है। प्रकोप अधिक होने की स्थिति में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बराइल (2.0 ग्राम/लीटर) या पडान (1.0 ग्राम प्रति लीटर) का 10 दिन के अंतर पर प्रयोग करें।

पाए जाने वाले पोषक तत्व

फाइबर: बैंगन फाइबर का अच्छा स्रोत है। फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहतर होता है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है।

पोटैशियम: बैंगन में पोटैशियम पाया जाता है, जो रक्तचाप के स्तर को कम करने में मदद करता है।

विटामिन बी कॉम्प्लेक्स: बैंगन में बी5 और बी6 जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। विशेष रूप से, बी-6 मस्तिष्क के न्यूरोट्रांस-मीटर संश्लेषण में भाग लेता है, जैसे कि सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और डोपामाइन, जो चिंता और भय को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं।

विटामिन सी: बैंगन विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, जो त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

प्रदूषणः कुछ दशकों में खत्म हो जाएंगे दुनिया के करीब 40 फीसदी कीट

गाड़ियों, फैक्ट्रियों, जंगल में धधकती आग आदि स्रोतों से निकलते प्रदूषण के महीन कण इंसानों के साथ-साथ अन्य जीवों को भी प्रभावित कर रहें है। कीटों को लेकर इस बारे में की गई एक नई रिसर्च से पता चला है कि प्रदूषण के यह कण कीटों के एंटीना और रिसेप्टर्स पर असर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इन नन्हें जीवों को अपना आहार, साथी, या अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह खोजने में दिक्कतें आ रही हैं।

रिसर्च के मुताबिक बढ़ता प्रदूषण ने केवल शहरों के आसपास बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी इनकी आबादी को प्रभावित कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर इनकी घटती संख्या की वजह बन सकता है। गौरतलब है कि धरती का करीब 40 फीसदी हिस्से में प्रदूषण के यह कण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय वार्षिक औसत मानकों से ज्यादा हैं। अध्ययन के अनुसार कीटों पर पड़ने वाला वायु प्रदूषण का असर अनुमान से कहीं ज्यादा है। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, बीजिंग वानिकी विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया डेविस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसके नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित हुए हैं।

इस बारे में मेलबर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता मार्क एल्गर का कहना है कि, हम जानते हैं कि प्रदूषण के कणों का सम्पर्क कीटों सहित अन्य जीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। हमारे अध्ययन में सामने आया है कि यह गंध की मदद से कीटों के भोजन और साथी को खोजने की महत्वपूर्ण क्षमता को भी सीमित कम कर देता है। उनके मुताबिक इसकी वजह से कीटों की आबादी में गिरावट आ सकती है। इतना ही नहीं रिसर्च से पता चला है कि जंगल में लगने वाली आग और उससे होता प्रदूषण, स्रोत से दूर भी कीटों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने बताया कि, आकर्षक होने के साथ-साथ यह कीट कई अन्य तरहों से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पौधों में परागण के लिए अहम होते हैं। इनमें करीब-करीब वो सभी फसलें शामिल हैं, जिन पर हम अपने आहार के लिए निर्भर करते हैं। इतना ही नहीं यह कीट सड़ती-गलती सामग्री के विघटन के साथ पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं। शोधकर्ताओं को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के उपयोग से पता चला है कि जैसे-जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता है, घरेलू मक्खियों के संवेदनशील एंटीना पर अधिक कण जमा होने लगते है।

कैसे प्रदूषण के यह कण कीटों की क्षमता को कर रहे हैं प्रभावित इन कणों में हवा में मुक्त हुए ठोस कण या तरल पदार्थ होते हैं, जिनमें कोयला, तेल, पेट्रोल या आग से पैदा हुई जहरीली भारी धातुएं और कार्बनिक यौगिकों

शामिल होते हैं। अध्ययन से पता चला है कि उनके एंटीना पर मौजूद इस प्रदूषण ने मक्खियों के मस्तिष्क को भेजे जाने वाले गंध-संबंधी विद्युत संकेतों की शक्ति को काफी कम कर दिया था, जो गंध का पता लगाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है।

बता दें कि कीटों के एंटीना में गंध को पकड़ने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो आहार स्रोत, संभावित साथी या अंडे देने के लिए एक अच्छी जगह को खोजने में कीटों की मदद करते हैं। ऐसे में यदि किसी कीट के एंटीना, पार्टिकुलेट मैटर से ढके होते हैं, तो उससे एक भौतिक अवरोध उत्पन्न जो जाता है जो गंध को पकड़ने वाले रिसेप्टर्स और हवा में मौजूद गंध के अणुओं के बीच होने वाले संपर्क को रोकता है। प्रोफेसर एल्गर का कहना है कि, जब उनके एंटीना प्रदूषण के कणों से भर जाते हैं, तो कीड़े भोजन, साथी या अपने अंडे देने की जगह को सूंघने के लिए संघर्ष करते हैं और इससे उनकी आबादी पर असर पड़ेगा।

उनके अनुसार, आश्चर्य की बात है कि हवा के जरिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाले इन कणों के कारण सुदूर और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। भले ही हमें इसका अहसास न हो लेकिन यह नन्हें जीव पर्यावरण, जैवविविधता और इंसानों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनकी भूमिका को इसी से समझा जा सकता है कि यह कीट 80 फीसदी से ज्यादा पौधों को परागित करते हैं, जो इंसानों समेत अनगिनत जीवों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। इसके बावजूद इन जीवों के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए गए हैं। नतीजन विविधता से भरपूर यह जीव तेजी से घटते जा रहे हैं। एक अन्य रिसर्च से पता चला है कि सभी जीवों में करीब 80 फीसदी आबादी कीटों की है। इसके बावजूद आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जारी की जाने वाली रेड लिस्ट में कीटों की केवल आठ फीसदी प्रजातियों का ही अध्ययन है। जर्नल साइंस में छपे एक अध्ययन के मुताबिक 1990 के बाद से कीटों की आबादी में करीब 25 फीसदी की कमी आई है। वहीं अनुमान है कि यह कीट हर दशक करीब नौ फीसदी की दर से कम हो रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में छपे एक शोध में भी इस बात की पुष्टि की थी कि कीटों की आबादी तेजी से घट रही है। शोध का अनुमान है कि ऐसा हो चलता रहा तो अगले कुछ दशकों में दुनिया के करीब 40 फीसदी कीट खत्म हो जाएंगें। वैज्ञानिकों के अनुसार कीटों की घटती आबादी के लिए काफी हद कृषि, शहरीकरण, प्रदूषण, कीटनाशक और जलवायु में आता बदलाव जैसी वजहें जिम्मेवार हैं।

यथार्थवादी परंपरा के ईमानदार कलमकार मुंशी प्रेमचंद

लक्ष्मी प्रसाद चौधरी
स्नातकोत्तर शिक्षक (हिंदी)
केंद्रीय विद्यालय काठमांडू, नेपाल

साहित्य में यथार्थवादी परंपरा की आधारशिला रखने वाले मुंशी प्रेमचंद बेहद ईमानदार कलमकार थे। ईमान की कलम में बहुत पैनी धार होती है, जो उनके साहित्य में दृष्टव्य है। यद्यपि प्रारंभिक रचनाओं में प्रेमचंद की लेखनी, कल्पना और रूमानियत के रंगों से जीवन-प्रसंगों को जीवंत करते रही तथापि समय की धारा के साथ उनके जीवन-संघर्षों ने उन्हें आदर्शोन्मुख यथार्थवादी और बाद में विशुद्ध यथार्थवादी बना दिया।

यदि यथार्थवाद और आदर्शवाद शब्दों के अर्थों पर गौर करें तो 'वास्तव में क्या है'-यह 'यथार्थवाद' है और 'क्या हो सकता है' वह आदर्शवाद। यथार्थवाद निराशा को जन्म देता है इसमें मनुष्य का मनुष्य पर संदेह पुष्ट हो जाता है और हर ओर बुराई का कीचड़ बदबू मारता है । सामाजिक ताने-बाने के यथार्थ के धरातल पर जहां 'पंच परमेश्वर' कहानी में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोका भी न सह सका; उनका मिलन तलवार की धार और म्यान का मिलन बन गया। कहानी के अंत में मित्रता की मुरझाई लता फिर हरी हो जाती है। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक बन जाता है। पंच की जुबान से खुदा बोलता है। यह प्रेमचंद का आदर्श है। 'प्रेमाश्रम' और 'सेवासदन' जैसे उपन्यास जहां एक ओर कटु यथार्थ को उकेरते हैं; वहीं दूसरी ओर सामाजिक समस्याओं और मूल्यों के अंतर्विरोध बाद में एक आदर्श समाधान के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं । 'सेवासदन' उपन्यास में देखा जा सकता है कि न चाहते हुए भी इंसान को परिस्थितियां कैसे पथभ्रष्ट बना देती हैं। उपन्यास की नायिका सुमन वेश्यावृत्ति के दलदल में फँस जाती है और फिर समय की मार के बाद चंचलता और तृष्णा को त्यागकर धन की अपेक्षा धर्म का आचरण करती है। आज भी समाज में ऐसी कई 'सुमन' हैं, जो समाज की मुख्यधारा से जुड़कर बहुत कुछ बेहतर करना चाहती हैं।

दशकों बाद भी बिखरते हुए परिवार को हमारे आदर्श मूल्य कैसे जोड़े रखते हैं? इस दृष्टि से 'बड़े घर की बेटी' कहानी आज भी प्रासंगिक है। भौतिक सुख-साधनों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति बेनी माधव सिंह की आर्थिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख देती है। जब बड़े घर की बेटी आनंदी से उसका देवर लालबिहारी शिकार करके लाई गई चिड़ियों का माँस पकाने को कहता है तब घर में रखा एक पाव घी मांस पकाने में ही खत्म हो जाता है और परोसी गई दाल में घी न पड़ने पर हुए विवाद में आग बबूला होकर अपनी खड़ाऊँ फेंककर भाभी को दे मारता है। यह बात आनंदी के पति श्रीकंठ को पता चली तो परिवार बिखराव की कगार पर आ जाता है। गांव के मौकापरस्त लोग इस बिखराव पर खूब रस लूटते हैं किंतु लालबिहारी के पश्चाताप के आंसू आनंदी के मन के क्लेश को धोकर दूर कर देते हैं । जिसके कारण रिश्ते दाँव पर लग गए थे वही रिश्तों को मजबूती देती है। ठीक इसी तरह 'माँ' कहानी के पात्र आदित्य के देश और समाज हित में सब कुछ होम कर देने वाले आचरण के विरुद्ध उसका पुत्र प्रकाश विलायती अंधकार की ओर आकर्षित हुआ तब उसकी मां करुणा की वेदना को पाठक समझ सकता है । बेटे को सही रास्ते पर लाने का करुणा का प्रयास आदर्श की ओर कथाकार का झुकाव है।

मुंशी प्रेमचंदजी की 'नमक का दरोगा' कहानी आज भी ईमानदार और कर्मठ व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करती है। कहानी में पंडित अलोपीदीन कहते हैं परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यह प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ही है; जो 'लॉटरी' जैसी कहानियों में थोड़ा कमज़ोर होकर यथार्थवाद की ओर कदम बढ़ाता है जिसमें पारस्परिक स्वार्थ के कारण लाटरी का लोभ परिवार और दोस्ती को तहस-नहस कर देता है । बाद में 'गोदान' जैसे आधुनिक क्लासिक उपन्यास में मरणासन्न विपन्न किसान से गौ दान कराना कटु यथार्थ की अभिव्यक्ति है। 'पूस की रात' कहानी में पूस की कड़कड़ाती ठंडी रात में खेत की रखवाली करते हुए मड़ैया में ठंड से बचने के लिए जबरे कुत्ते को अपनी गोद में चिपकाए रखना और उसकी दुर्गंध को भी सहन करके गर्मी का एहसास करना और नीलगायों के द्वारा खेत का सफाया करने के बावजूद खुश होना कि रात को ठंड में खेत में सोना तो नहीं पड़ेगा। इसी तरह कफन कहानी में उपन्यास सम्राट का आदर्श तार-तार हो गया।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस भारत में हेपेटाइटिस बी से चार करोड़ लोग संक्रमित

हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस आयोजित किया जाता है। संक्रामक रोगों का एक समूह जो लीवर या यकृत पर हमला करता है और दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करता है। यह दिन सभी पांच प्रकार की बीमारियों जिसमें ए, बी, सी, डी और ई के परीक्षण और रोकथाम को भी बढ़ावा देता है।

लीवर की सूजन को आमतौर पर हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस एक व्यापक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी और ई के कारण होता है। लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस या लिवर कैंसर में बदल सकता है। हेपेटाइटिस लीबर को तबाह कर सकता है। आपका लीवर आपको जीवित रखने के लिए हर दिन चुपचाप 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, संक्रामक हेपेटाइटिस संक्रमण भी शांत होता है, लक्षण बीमारी बढ़ने पर ही दिखाई देते हैं। यद्यपि हेपेटाइटिस वायरस (ए से ई) के कई अलग-अलग प्रकार हैं, हेपेटाइटिस बी और सी सबसे अधिक चिंताजनक हैं और हर दिन लगभग 8,000 नए संक्रमणों का कारण बनते हैं, जिनमें से अधिकांश का पता नहीं चल पाता है। हर साल हेपेटाइटिस से संबंधित 10 लाख से अधिक मौतें, और हर दस सेकंड में एक नया संक्रमण सामने आता है। इसलिए लीवर का स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य के लिए अहम है। हेपेटाइटिस से होने वाली बहुत सी मौतों को रोका जा सकता है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी के लिए टीके और प्रभावी उपचार हैं और यहां तक कि हेपेटाइटिस सी का इलाज भी है। हेपेटाइटिस से खुद को कैसे बचाएं, यह जानने के लिए अपने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस का इतिहास: विश्व हेपेटाइटिस एलायंस ने इस दिन की स्थापना 2008 में की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मूल रूप से 19 मई को आयोजित किया गया था। 2010 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अमेरिकी चिकित्सक डॉ. बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग के जन्मदिन को मनाने का निर्णय लेने के बाद यह तिथि 28 जुलाई कर दी गई। जिन्होंने साठ के दशक में हेपेटाइटिस बी की खोज की थी और अंततः वायरस और इसके टीके पर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम: इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम एक जीवन, एक लीवर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में, संक्रामक हेपेटाइटिस अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचाना जाता है। डब्ल्यूएचओ के नवीनतम अनुमान के अनुसार, भारत में चार करोड़ लोग लंबे समय से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं और 60 लाख से 1.2 करोड़ लोग लंबे समय तक हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि, 2030 तक वैश्विक उन्मूलन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए परीक्षण और उपचार का कम कवरेज सबसे बड़ा अंतर है, जिसे हल किया जाना चाहिए।

कायम की मिसाल: मऊगंज जिले की देवरी शिवमंगल सिंह में स्वयं के व्यय पर बनवाई सड़क

निर्मल पंचायत की महिला सरपंच ने लिखी विकास की नई इबारत

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में एक तरफ जनप्रतिनिधि जहां शासन से पैसे का इंतजार करते हैं और पौसा आने तक संबंधित क्षेत्र की जनता कष्ट भोगती है। ऐसे में एक ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने जन सेवा का नया उदाहरण पेश किया है। इस महिला सरपंच ने बता दिया कि मन से जुड़ाव जनता से है। इसमें धन कोई मायने नहीं रखता। राष्ट्रपति के हाथ निर्मल ग्राम पंचायत का पुरस्कार पा चुकी महिला सरपंच ने विकास के लिए एक नई इबारत गढ़ दी है। जिस इबारत का पाठ प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर, सरपंच, पार्षदों, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष को पढ़ाया जाना चाहिए।

तीन लाख की लागत से बनी गांव में सड़क

नवनिर्मित सड़क की अनुमानित लागत तीन लाख रुपए बताई जा रही है। सड़क का निर्माण होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की सरपंच गृहपा सिंह ने अपने पूर्व के कार्यकाल में भी राष्ट्रपति के हाथों निर्मल ग्राम पंचायत का पुरस्कार पाकर समूचे मध्यप्रदेश में पंचायत का नाम रोशन किया था। जबकि वर्तमान में उन्होंने अपने स्वयं के व्यय पर एक किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा कर ग्राम पंचायत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। अब गांव के लोगों को बरसात के दिनों में सड़क की कमी नहीं खलेगी।

मुख्य मार्ग से जुड़ी पंचायत

दरअसल, मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले की जनपद पंचायत मऊगंज की ग्राम पंचायत देवरी शिवमंगल सिंह में विकास की अनोखी झलक देखने को मिली। यहां की महिला सरपंच गृहपा सिंह ने अपने गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक किमी लंबी सड़क का निर्माण स्वयं के व्यय पर करा दिया। पंचायत के गांवों को मऊगंज जिले से जोड़ने वाले इस मार्ग के निर्माण से जहां समूचा गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। साथ ही गांव के लोगों का आवागमन भी सुगम हो जाएगा। बरसात में होने वाली परेशानी भी दूर हो गई है।

जागत गांव के सवाल-सरपंच के जवाब

सवाल: अपने पैसे से सड़क बनाने का आपका उद्देश्य क्या है?

जावाब: इसमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। असल में हमारी पंचायत में आजादी के बाद से आज तक सड़क नहीं थी। जब हमने जिला और जनपद में मांग की तो हमारे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। इसलिए मैंने अपने पैसे से सड़क बनवा दी।

सवाल: सड़क निर्माण में व्यय राशि का क्या भुगतान नहीं कराएंगी?

जवाब: नहीं, मैं इस राशि के भुगतान के लिए कहीं बिल नहीं लगाऊंगी। मेरा जो लक्ष्य था वो सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए।

सवाल: इस सड़क के बनने से कितनी आबादी को लाभ मिलेगा?

जवाब: इस सड़क के बन जाने से हमारी पंचायत के साढ़े तीन हजार लोग मुख्य मार्ग से जुड़ गए हैं। साथ ही अन्य गांवों को भी इसका लाभ मिलेगा।

सवाल: कभी स्थानीय विधायक से सड़क निर्माण की आपने मांग नहीं की?

जवाब: सड़क निर्माण के लिए हमने स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल से मांग किए थे। वे सड़क निर्माण के लिए हमारे साथ तीन घंटे धरने पर भी बैठे थे। इसके बाद भी हमारे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं प्रदान की गई।

सवाल: अब आप विधायक से क्या अपेक्षा रखती हैं?

जवाब: हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मप्र में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। हर जगह पक्की सड़कें बन रही हैं। मैं चाहती हूं कि विधायक जी प्रयास करें तो इस सड़का का भी डामरीकरण हो सकता है। विधायक निधि से भी करा सकते हैं।

विजयराघवगढ़ वेयर हाउस में सबसे ज्यादा हुआ खराब

जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान हो रहा

कटनी में 69 करोड़ का 73 हजार मैट्रिक टन गेहूं बर्बाद

कटनी। जागत गांव हमार

शासकीय उचित मूल्य की दुकान (पीडीएस) के माध्यम से गरीबों को बटने वाले गेहूं की सुरक्षा को लेकर जिले में बड़ी बेपरवाही सामने आई है। जिम्मेदार विभाग गरीबों के निवाले को सुरक्षित नहीं रख पाए हैं। अब आलम यह है कि दिन प्रतिदिन गेहूं कीड़ा लगने के कारण बर्बाद हो रहा है। कुछ जगह पर तो आटा में तब्दील हो गया है। जिले के वेयर हाउसों में भंडारित 73 हजार 261 मैट्रिक टन गेहूं खराब हो गया है। कीड़े (पाई) लगने के कारण गेहूं आटा बन रहा है। 2019-20 से लेकर पिछले साल तक का गेहूं भंडारित है। खराब हुए गेहूं की कीमत 68 करोड़ 90 लाख 66 हजार 250 रुपए है। सुरक्षा और संरक्षा में 20 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं वह अलग। सरकार से लाखों रुपए किराया लेने के बाद भी अनाज की सुरक्षा न तो वेयर हाउस मालिकों ने की और ना ही जिम्मेदार विभाग वेयर हाउस प्रबंधन, नागरिक आपूर्ति निगम, जिला प्रशासन करा पाया। समय पर फ्यूमीगेशन व उठाव न होने के कारण यह स्थिति बनी है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार विभाग भी मामले को दबाने में जुटे हुए हैं।

जानकारी के अनुसार जिले के आधा दर्जन से अधिक वेयर हाउसों में गेहूं खराब हुआ है। तीन वेयर हाउसों में रखा गेहूं सबसे अधिक मात्रा में खराब हुआ है। शहर के पुरैनी स्थित केजी चौदहा वेयर हाउस, बरही क्षेत्र के उबरा वेयर हाउस, विजयराघवगढ़ वेयर हाउस सहित श्रीनिवास, श्रीजी, श्रीनाथ, श्याम्भवी, मोहन, डीएम, ओम साईराम वेयर हाउस में सर्वाधिक भंडारित गेहूं खराब हो चुका है, लेकिन उसकी न तो अबतक गुणवत्ता ठीक कराई गई और ना ही उठाव कराया गया।

नान ने नहीं कराया उठाव

जानकारी के अनुसार समय रहते नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा गेहूं का उठाव नहीं कराया गया। पहले उठाव नहीं कराया गया फिर कीड़ा लगने के कारण समय पर फ्यूमीगेशन व साफ न कराए जाने के कारण गेहूं खराब होता चला गया और पांच साल बाद भी उसका उठाव न होने से वह उपयोग लायक नहीं बचा है। नागरिक आपूर्ति निगम को वेयर हाउस प्रबंधन द्वारा पुराने वित्तीय वर्ष का माल उठवाने के लिए कई बार पत्राचार किया गया है। समय पर उठाव न होने से गुणवत्ता ह्रास भी हो रहा है, नान न तो माल उठवा रही है और ना ही पत्राचार का कोई जवाब दे रहा।

सुरक्षा पर भी सवाल

हैरानी की बात तो यह है कि वेयर हाउस मालिकों के द्वारा भी अनाज की सुरक्षा पर ध्यान नहीं रखा गया। सरकार द्वारा वेयर हाउस मालिकों को 2019-20 में 55 रुपए, 2020-21 में 62 रुपए, 2021-22 में 85 रुपए, वर्तमान में 67 रुपए प्रति मैट्रिक टन का भुगतान किया जा रहा है, बावजूद इसके गरीबों के निवाले को संभालकर नहीं रखा गया।

नागरिक आपूर्ति निगम को नियमित रूप से 2020 से समय पर गेहूं का उठाव के लिए पत्राचार किया जा रहा है। 75 हजार मैट्रिक टन से अधिक गेहूं पुराने वित्तीय वर्षों का भंडारित है। समय पर उठान न होने से गेहूं की गुणवत्ता खराब हो रही है।

वायएस सेंगर, डीएम वेयर हाउस प्रबंधन

गोदामों में गेहूं की सुरक्षा नहीं हो पाई, जिससे वह खराब हुआ है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण गेहूं का उठाव नहीं कराया गया। कुछ गोदामों में डीसीसी की भी प्रक्रिया हो चुकी है।

अमित गौड़, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम

खराब गेहूं की स्थिति (मैट्रिक टन में)

वर्ष	भंडारण	मूल्य
2019-20	17354	31931600
2020-21	25288	48679400
2021-22	21294	420556500
2022-23	9325	187898750

भंडारण में दे रहे करोड़ों रुपए किराया

2019-20 के भंडारित गेहूं में अबतक तीन करोड़ 81 लाख 7 हजार 880 रुपए से अधिक का भुगतान, 2020-21 के भंडारित गेहूं में गोदामों का किराया 4 करोड़ 70 लाख 3 हजार 568 रुपए से अधिक, 2021-22 में भंडारित गेहूं में 3 करोड़ 61 लाख 9 हजार 980 रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। इसके अलावा 2022-23 में खरीदे गए गेहूं के भंडारण का साढ़े 12 लाख 49 हजार 550 रुपए से अधिक दिए जा चुके हैं। कुछ वेयर हाउसों में दो माह से किराया का भुगतान अटका है।

जिलेभर की गोदामों में भंडारित गेहूं जो खराब हो चुका है उनके भंडारण व सुरक्षा में 20 करोड़ रुपए से अधिक फूंके जा चुके हैं। सरकार ने अकेकेले गोदाम मालिकों को अबतक 13 करोड़ 39 हजार 978 रुपए का भुगतान कर चुकी है।

मुख्यमंत्री चौहान ने की समीक्षा, कहा

प्रदेश में किसानों को दो लाख टन खाद अधिक मिलेगी

भोपाल। खरीफ की फसल के लिए इस बार किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में दो लाख टन खाद ज्यादा मिलेगी। सरकार ने कोटा 14 लाख टन से बढ़ाकर 16 लाख टन कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में खरीफ और आगामी रबी फसलों की तैयारी के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था रहे। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरभाष पर बात कर प्रदेश में केंद्र सरकार से खाद की आपूर्ति का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिस जिले से भी मांग आए, वहां पर्याप्त खाद पहुंचाएं। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खाद की मांग की जाए। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गौशालाओं के निर्माण में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में गायें सड़कों पर हैं, जिन्हें गोशालाओं में पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। गोशालाएं बनाने के काम में बहुत तेजी लाएं। अस्थायी रूप से भी गायों को रखने की व्यवस्था करें। गौशालाओं के निर्माण एवं गोवंश की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर स्थान चिह्नित कर लें। गोशालाओं के निर्माण और गायों के रखने की व्यवस्था के संबंध में कार्ययोजना बनाकर काम शुरू करें।

मध्यप्रदेश में मूंग और उड़द खरीदी की तारीख बढ़ाई

अब सात अगस्त तक उपज बेची जा सकेगी

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब मूंग और उड़द की खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। अब किसान आगामी सात अगस्त तक अपनी उपज बेच सकेंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस संबंध में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द खरीदी की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2023 से बढ़ाकर किसान भाइयों-बहनों के हित में 7 अगस्त 2023 तक करने का निर्णय लिया है। अब किसान अपने स्लाट 31 जुलाई तक बुक कर सकते हैं। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

1011 करोड़ की बहोरीबंद सिंचाई परियोजना स्वीकृत

सीएम शिवराज बोले पुरानी सरकार ने बंद की जन-कल्याण की अनेक योजनाएं

कटनी के हर खेत को सिंचाई का पानी और हर घर को नल से मिलेगा जल

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से हर खेत तक पानी और जल-जीवन मिशन द्वारा हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। कटनी क्षेत्र के लिए 1011 करोड़ रुपए की बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। परियोजना से 80 हजार एकड़ में सिंचाई होगी और कटनी तहसील के 5, बहोरीबंद के 86 गांव, रीठी के 17 और स्लीमनाबाद के 43 गांवों को पानी मिलेगा। जल-जीवन मिशन से कटनी जिले में रीठी जनपद के 109 और कटनी जनपद के 50 ग्रामों सहित जिले के पठारी क्षेत्र के 159 गांवों में अब आसानी से घर-घर नल से जल पहुँचेगा। मुख्यमंत्री कटनी जिले के बड़गांव में क्षेत्र के 313 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहनों के सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 45 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मी हैं और लगभग 1.25 करोड़ लाड़ली बहनें हैं। अब 21 वर्ष की बहनों और ट्रेक्टर वाले 5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवार की बहनों को भी लाड़ली बहना योजना की पात्रता है। पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण आज बहनें सरकार चला रही हैं। आज यहां मंच पर 23 वर्ष की सरपंच बिटिया और कटनी की महापौर बहन बैठी हैं। यह हमारे लिये गौरव की बात है। लाड़ली बहना योजना की राशि को धीरे-धीरे बढ़ा कर 3000 रुपए तक किया जाएगा।

हम सभी विशाल परिवार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी विशाल परिवार हैं। प्रदेश में सरकार नहीं परिवार चल रहा है। जिस प्रकार एक परिवार में हर सदस्य के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार प्रदेश में भी हर व्यक्ति के कल्याण के कार्य किये जा रहे हैं। गरीब किसान भाइयों को वर्ष में मिलने वाली सम्मान निधि की राशि 12 हजार रूपये कर दी गई है। गरीब को प्रतिमाह 5 किलो नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना में वर्ष में 5 लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था है।

डिफाल्टर किसानों का हमने भरा कर्ज

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार ने जन-कल्याण की बहुत सी योजनाएं बंद कर दीं। किसानों के साथ कर्ज माफी का झूठा वादा कर उन्हें डिफाल्टर बना दिया। हमारी सरकार ने किसानों का 2200 करोड़ रुपए का ब्याज भर कर उन्हें ऋण मुक्त किया है और शून्य प्रतिशत ब्याज पर उन्हें फसल ऋण दिया जा रहा है। पुरानी सरकार ने संबल और तीर्थ-यात्रा बंद कर दी तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि नहीं दी। हमारी सरकार ने सभी योजनाएँ दोबारा चालू की। अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ-दर्शन कराया जा रहा है।

उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरवाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बेटे-बेटियों की पढ़ाई में पैसों की बाधा नहीं आने दूंगा। बच्चों को किताब, गणवेश, सायकल, लेपटॉप और अब टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी भी दी जाएगी। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरवाएगी। प्रदेश में एक लाख पदों पर सरकारी भर्ती की जा रही है, स्व-रोजगार के लिए ऋण दिलाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में प्रशिक्षण के साथ मानदेय भी दिया जा रहा है। हर हाथ को कार्य दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुष्पवर्षा कर बहनों का अभिनंदन किया। बहनों ने अपने लाड़ले मुख्यमंत्री भाई को राखी बांधी। सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन-स्तर को बेहतर बनाना है। बहोरीबंद विधायक श्री प्रणय पांडे ने स्वागत उद्बोधन दिया। प्रदेश के वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक संजय पाठक, संदीप जायसवाल, दीपक सोनी टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा, कटनी महापौर प्रीति संजीव सूरी मौजूद रहीं।

चिरौंजी को व्यावसायिक तौर पर और अधिक मजबूत बनाने दिए दो लाख

सीएम ने चिरौंजी बेचकर आत्मनिर्भर बन रहे आदिवासियों की उद्यमिता को सराहा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़गांव में आयोजित रोड शो के दौरान वनोपज चिरौंजी बेचकर आत्मनिर्भर बन रहे निपनिया और केवलारी गांव के जनजाति समाज से भेंट की। मुख्यमंत्री ने जनजातियों द्वारा किए जा रहे चिरौंजी की बिक्री के कार्य के व्यावसायिक रूप से और अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए दो लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। जनजातीय समाज ने मुख्यमंत्री को चिरौंजी का पैकेट उपहार स्वरूप प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में उठाए गए प्रयासों के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री से रोड शो के दौरान मिले निपनिया और केवलारी के जनजातीय समाज ने बताया कि कृषि विभाग की आत्मा परियोजना की मदद से रानी दुर्गावती बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन कर चिरौंजी प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने के बाद उन्हें चिरौंजी की अच्छी कीमत मिलना शुरू हुई। मुख्यमंत्री यह सुनकर बेहद खुश हुए। उन्होंने समिति के सदस्य महेश सिंह और मदन उरेती से बात कर अचार की गुठलियों से चिरौंजी निकालने तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली।

जनजातीय बंधुओं ने मुख्यमंत्री को चर्चा के दौरान बताया कि प्रसंस्करण यूनिट लगने के पहले तक व्यापारी और साहूकार उनसे मात्र 100 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से चिरौंजी खरीदते थे और खुद चिरौंजी को खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब वे खुद चिरौंजी की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करते हैं और सौ ग्राम चिरौंजी 180 रूपए में बेचते हैं। मुख्यमंत्री ने जनजातीय वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिये प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा की।

बिचौलियों की बंद कर दी दुकान

जिले के बहोरीबंद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निपानिया और केवलारी ग्राम के करीब 400 जनजातीय परिवार आस-पास के वन में लगे अचार वृक्ष से चिरौंजी की गुठलियों को तोड़कर वर्षों औने-पौने दामों में व्यापारियों को बेचते रहे हैं। व्यापारी भी उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें बहला-फुसलाकर, इनसे महंगी चिरौंजी को मात्र सौ रुपए प्रति किलो ग्राम की सस्ती कीमत में खरीदकर खुद खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, जनजातियों ने प्रशासन की मदद से समिति बनाकर खुद की प्रसंस्करण इकाई लगाई और अब खुद चिरौंजी की पैकेजिंग और बिक्री कर आमदनी अर्जित कर रहे हैं।

श्री अन्न को सही तरीके से बाजार में उतारा जाए तो मिलेगा अच्छा मूल्य

जबलपुर। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के तहत श्री अन्न खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. जीके कौतू ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती तो की जा रही है, लेकिन उसका किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा ऐसे में कोदो, कुटकी, रागी, सावां सहित अन्य मोटे अनाज की फसलों की खेती करने वाले किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने और उत्पादन को बेहतर दाम में बेचकर आर्थिक उन्नति के विभिन्न तौर तरीके प्रशिक्षण में सिखाये जा रहे हैं। जो कि सभी महिला कृषकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ. पीबी शर्मा ने कहा कि मोटे अनाज को ही श्री अन्न का नाम दिया गया है। गेहूं, चावल से ज्यादा फायदे की खेती श्री अन्न कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा की है। जिसे सही तरीके से अगर तैयार करके बाजार में उतारा जाए तो बहुत ही अच्छा मूल्य प्राप्त होगा।

महिलाओं को किया दक्ष

विभागाध्यक्ष डॉ. एसएस शुक्ला ने परियोजना प्रशिक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में मिलेट्स को लेकर ग्रामीणों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में डिण्डोरी जिले की बीजाडांडी ग्राम की 30 से अधिक महिला कृषक भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण में श्री अन्न की मशीनों द्वारा दराई, सफाई एवं प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण तकनीक, बेकरी उत्पाद बनाने की तकनीक, श्री अन्न के मूल्य संबंर्धित उत्पाद एवं विपणन, श्री अन्न के विपणन हेतु उद्यमिता, स्व-सहायता समूह के माध्यम से कैसे करें, दैनिक भोजन में श्री अन्न की भूमिका आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालयः राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए रवाना

प्रदेश के 18 होनहार ऑस्ट्रेलिया-फिलीपींस में पढ़ेंगे खेती का पाठ

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजभवन से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के विद्यार्थियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से संचालित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के संस्थान विकास कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 18 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। इनमें से आठ विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में और 10 विद्यार्थी फिलीपींस के उच्च कृषि शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, विद्यार्थियों के माता-पिता, पालक, कुलपति डॉ अरविन्द कुमार शुक्ला एवं प्राध्यापक मौजूद थे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विद्यार्थियों और पालकों से चर्चा की। छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। माता-पिता से सतत संवाद करते रहने के लिए कहा। पालकों को बच्चों का निरंतर उत्साह वर्धन करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल को विश्वविद्यालय की शोध गतिविधियों की जानकारी दी गई। श्री अन्न अथवा मिलेट्स की विभिन्न प्रजातियों के नमूने दिखाए गए।

उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से गार्गी त्रिपाठी गईं फिलीपींस

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी आस्ट्रेलिया जाने वालो में कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से निखिल खरे, कशिश यादव, शिवराज सिंह पोसवाल, आलोक चतुर्वेदी, कृषि महाविद्यालय सीहोर से तनु सिसौदिया, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से सुरभि आचार्य और कृषि महाविद्यालय, इंदौर से निकिता सोलंकी और आदेश कनेल शामिल हैं। आईआरआरआई मनीला फिलीपींस जाने वालों में कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से स्नेहा विश्वास, स्नेहा शर्मा, सुरंजना कुमारी, प्राजिक्ता कटारे, कृषि महाविद्यालय इंदौर से जयदीप पाठक, मुनीरा कौसर अंसारी, मरीना वीएल, कृषि महाविद्यालय सीहोर से श्रुति तोमर, कृषि महाविद्यालय खण्डवा से अनुराग शर्मा और उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से गार्गी त्रिपाठी शामिल हैं।

केवीके में किसानों को दिखाया सम्मान निधि का कार्यक्रम

किसानों को तकनीकी ज्ञान के साथ वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती करने का दिया सुझाव

कटनी। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कटनी में राजस्थान के सीकर से प्रधानमंत्री द्वारा सुबह 11 बजे किसानों को पी एम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी की गई, जिसका सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र, कटनी में रखा गया। कार्यक्रम में कुल 152 सदस्यों ने भाग लिया।

किसानों, केंद्र स्टाफ, एफपीओ, एनजीओ के पदाधिकारियों ने भागीदारी की। कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एके तोमर के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र कटनी के वैज्ञानिक डॉ. आरपी बेन, डॉ. केपी द्विवेदी संदीप चंद्रवंशी प्रियंका धुर्वे उपस्थित थे। कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के साथ ही जिले के प्रगति शील कृषकों ने कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एके तोमर ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड , एवं माइनर मिलेट्स फसलों के उत्पादन तकनीकी पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही किसानों को इस अवसर पर सलाह दी कि ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी का सफल उत्पादन कर अपने भोजन में गुणवत्ता लाएं और इसका सेवन करें। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आरपी बेन ने खरीफ की फसल धान तिल अरहर की उत्पादन तकनीकी जानकारी दी। पौध संरक्षण की विधियां बतलाई। डॉ. केपी द्विवेदी ने प्राकृतिक खेती की तकनीकी पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उसको बनाने की विधि पर सुझाव दिया। डॉ. संदीप चंद्रवंशी ने मौसम की महत्वता एवं मौसम के अनुसार फसल उत्पादन करने की किसानों को सलाह दी।

रीवा के किसानों ने पीएम मोदी को वर्चुअल देखा और सुना भी

रीवा। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा में पीएम किसान सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन हुआ। जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा करोड़ों किसानों के खाते में राशि एक क्लिक द्वारा राजस्थान के सीकर जिले से डाली गई। कार्यक्रम को जिले से आए किसानों और कृषि अधिकारियों के साथ साथ वैज्ञानिकों एवं छात्र छात्राए को प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा दिए गए उद्बबोधन को वर्चुअल माध्यम से सुनाया और दिखाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, जिला कृषि स्थाई समिति रीवा मप्र एवं विशिस्ट अतिथि डॉ. एसके पयासी कृषि महाविद्यालय रीवा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्र के प्रभारी एके पटेल ने की। कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय के प्रध्यापकगण डॉ. आरपी जोशी डॉ. एसके त्रिपाठी, उप संचालक कृषि यूपी बागरी, संजय श्रीवास्तव प्रचार्य, एफ टी सी, रीवा, केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. सीजे सिंह, डॉ. किंजल्क सिंह डॉ. राजेश सिंह, डॉ. बीके तिवारी, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. स्मिता सिंह, डॉ. संजय सिंह, संदीप शर्मा, एम के. मिश्रा, मंजू शुक्ला, ऋषभ विश्वकर्मा, कृषक एवं कृषि छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. बीके तिवारी और धन्यवाद डॉ. संजय सिंह ने किया।

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में प्रदर्शित इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया

छतरपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव, जिला छतरपुर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉ. दिनकर प्रसाद शर्मा (संचालक विस्तार सेवाएं) उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. राजीव कुमार सिंह ने रबी मौसम 23 में किए गए कार्यों की प्रगति एवं खरीफ मौसम 2023 की प्रस्तावित कार्ययोजना को पीपीटी(प्रेजेन्टेशन) के माध्यम से विस्तार से बताया गया। डॉ. कमलेश अहिरवार वैज्ञानिक (उद्यानिकी) के द्वारा मंच का संचालन किया गया। साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रदर्शित इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया। इस कार्यक्रम में लाइन डिपार्टमेंट से प्राचार्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र से प्राचार्य डॉ. केके वैध, उपसंचालक मत्स्य से बीएल अहिरवार ने भाग लिया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से सहायक संचालक डॉ. सुरेश कुमार पटेल, सहायक संचालक उद्यानिकी बी एस सेगर, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी से सहायक संचालक कृषि डॉ. प्रतीक कुमार भट्ट,सहायक संचालक कृषि अभियांत्रिकी से हेमंत कुमार बीज निगम अधिकारी योगेन्द्र नायक, महिला बाल विकास अधिकारी अनिल नामदेव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सूरज भान पटेल, उद्यानिकी विस्तार अधिकारी अर्जुन सिंह आदि शामिल हुए। कार्यक्रम में कुल 45 अधिकारी एवं किसानों की उपस्थिति रही।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

₹ 3000 तक बढ़ेगी राशि

21 वर्ष से ही मिलेगा लाभ

1 करोड़ 25 लाख बहनों को हर महीने ₹ 1000

राजकुमारी
चकरपुर गांव, निवाड़ी
"योजना के एक हजार मैं अपने परिवार पर खर्च करूंगी। मेरे खाते में पैसा होगा तो जब जरुरत पड़ेगी तब खर्च करूंगी।"

मृदुलेश शुक्ला
बड़ा बाजार, पन्ना
"मुख्यमंत्री जी इस योजना में जो राशि हमें दे रहे हैं उससे बच्चों को पढ़ाई और घर में पौष्टिक खाने के खर्च में मदद मिलेगी।"

मोनालिसा मिश्रा
कुदरा टोला, शहडोल
"हम बहनों के लिए एक सीधी सच्ची योजना की जरुरत थी। सीधे हमारे खाते में पैसे आएंगे। हमारा मान-सम्मान बढ़ेगा।"

अनीता विश्वकर्मा
संकटमोचन कॉलोनी, राजगढ़
"मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री जी की यह योजना मेरे लिए वरदान से कम नहीं है।"

चाहना
बिरसा मुण्डा वार्ड, कटनी
"मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी की इस योजना से हमारे पूरे घर में खुशी है।"

संपर्क : ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय और जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800

D-18466/23

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)